Simla Agreement. There can be no role for any third party.

Decision of G-15 Summit to develop ties with G-7

5612. SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the G-15 Summit held recently in New Delhi decided to develop ties with G-7 ;

(b) if so, the details of the deliberations and decisions taken therein ; and

(c) what steps are being taken in pursuance thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) : (a) Yes, Sir.

(b) The Summit decided that the G-15 initiative on a constructive and focussed dialogue with the G-7 which has been on going for the last two years would be carried forward.

(c) As per practice, our Prime Minister as the Chairman of the Fourth G-15 Summit, is sending the Joint Communique approved by the Summit to the Prime Minister of Italy, the present Chairman of G-7, for circulation to the Heads of State/Government of G-7 countires. This will be followed by a message form the next Chairman of the G-15 to his G-7 counterpart, nearer the time of next G-7 Summit, on issues of common interest to both groups.

चकमा-शरणार्थियों पर व्यय की गई धनराशि

5613. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग पिछले एक दशक की अवधि के दौरान चकमा आदिवासियों की समस्या के समाधान हेतु बांगला देश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के सात दौर हो चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इन वार्ताओं के फलस्वरूप अब तक इस समस्या का कोई समाधान निकला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या जानकारी है तथा मार्च, 1994 के अंत तक, भारत सरकार द्वारा चकमा-शरणार्थियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) त्रिपुरा से चकमा तथा अन्य जनजातीय शरणार्थियों को बंगला देश प्रत्यावर्तित करने के मामले पर भारत सरकार तथा बंगला देश की सरकार के बीच विगत में कई अवसरों पर बातचीत होती रही है । मई, 1992 में बंगला देश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सभी चकमा शरणार्थियों के शीघ्र प्रत्यावर्तन की व्यवस्था पूर्ण हिफाजत तथा सुरक्षा के माहौल में की जायेगी । बंगला देश के संचार मंत्री कर्नल ओली अहमद 2 से 9 मई, 1993 तक भारत की यात्रा पर आये थे । और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार के साथ बातचीत करने के साथ-साथ शरणार्थियों को अपने देश में लौटने के लिये राजी करना भी था । इसके बाद बातचीत के कई दौर हुये जिनके परि-